

लोकसभा उपाध्यक्ष

प्रलिस के ललल:

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद: नलल, संवैधानकल प्रावधान और अधलशल, संसद के पीठासीन अधिकारलल के ललल प्रावधान, अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 95

मेन्स के ललल:

उपाध्यक्ष का महत्त्व

[स्रोत: द हल्लु](#)

चरचा में कूल?

लोकसभा की कार्यपद्धतल में नषलषकषता और नरलतरता सुनशलचलतल करने हेतु संवैधानकल रूप से परकललपतल पद महत्त्वपूर्ण होने के बावजूद, लोकसभा उपाध्यक्ष का पद **17वीं लोकसभा** के दौरान रकलत रहा तथा 18वीं लोकसभा में भी रकलत है।

- यदयपल संवधान में नललकृतल के ललल कोई नशलचलतल समय-सीमा नरलधारलतल नहीं की गई है, कतु अनुच्छेद 93 और 178 में वनलरलदषलट "चुनेगी" और "यथाशक्य शीघ्र" पदों का प्रयोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन को अनवलर्य बनाता है।

लोकसभा उपाध्यक्ष के पद से संबंधलत प्रमुख प्रावधान कूल हैं?

- संवैधानकल प्रावधान:
 - अनुच्छेद 93: इसमें प्रावधान है कल लोकसभा को यथाशीघ्र सदन के दो सदसूलों को करमश: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनना होगा।
 - अनुच्छेद 94: इसमें लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रकलत होने, पद त्याग और पद से हटाए जाने संबंधी प्रावधान कलल गए हैं।
 - अनुच्छेद 95(1): अध्यक्ष का पद रकलत होने पर लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कर्तवूलों का नरलवहन करेगा तथा सदन की अध्यक्षता करते हुए पद की शक्तललल का प्रयोग करेगा।
 - नललमें में "अध्यक्ष" के सभी संदर्भों को उप-अध्यक्ष के ललल भी संदर्भ माना जाएगा, उस समय के ललल जब वह अध्यक्षता करते हैं।
 - अनुच्छेद 178: इसमें राज्य वधानसभाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के ललल तत्संबंधी प्रावधान है।
- चुनाव प्रक्रलल:
 - लोकसभा उपाध्यक्ष (अध्यक्ष सहलतल) का चुनाव लोकसभा के सदसूलों में से उपस्थलतल और मतदान करने वाले सदसूलों के साधारण बहुमत द्वारा कलल जाता है।
 - यह चुनाव [लोकसभा के प्रक्रलल और कार्य संचालन के नललमें](#) द्वारा वनलललमतल होता है।
 - अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तथलकल नरलधारण करता है।
 - वपलकषी दल ने कई बार लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद ग्रहण कललल है। (लेकनल यह न तो संवधान द्वारा और न ही कसीं कानून द्वारा अनवलर्य है, यह मातृ परपलटी है)।
 - उदाहरण के ललल UPA-I (वर्ष 2004-09) और UPA-II (वर्ष 2009-14) सरकारों के साथ-साथ अटल बहलरी वाजपेयी (वर्ष 1999 से 2004), पी वी नरसमलहा राव (वर्ष 1991-96) और चंदरशेखर (वर्ष 1990-91) के कार्यकाल के दौरान।
 - अलग से शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है; केवल तीसरी अनुसूची के तहत सांसद की शपथ ही पर्याप्त है।
- कार्यकाल और नषलकासन:
 - उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की तरह, लोकसभा के कार्यकाल तक पद धारण करता है लेकनल नमलनलखलतल मामलों में वह इसे पहले भी रकलत कर सकता है:
 - लोकसभा सदस्य नहीं रह जाता है;
 - अध्यक्ष को पत्र लखलकर त्यागपत्र देता है;

- 14 दिन की पूर्व सूचना पर कुल लोकसभा सदस्यों के बहुमत (पूर्ण बहुमत) द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया गया हो।
- जब भी लोकसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो लोकसभा उस पद को भरने के लिये एक नए सदस्य का चुनाव करती है।

लोकसभा उपाध्यक्ष के पद से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है?

- लोकसभा उपाध्यक्ष का पद ब्रिटिश शासन के तहत केंद्रीय विधान सभा में शुरू हुआ था। सचचिदानंद सनिहा वर्ष 1921 में इस पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति थे।
- स्वतंत्रता के बाद एम. अनंथशयनम अयंगर भारत की लोकसभा के पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष बने।
 - वर्ष 1956 में लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर के निधन के बाद, अयंगर ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और बाद में वे दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए।

लोकसभा उपाध्यक्ष के पद का क्या महत्त्व है?

- विधायी नरितरता सुनिश्चित करना: उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के साथ प्रक्रियात्मक व्यवस्था बनाए रखता है और विधायी नषिक्रयिता को रोकता है।
- संवैधानिक अधिकार: अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा उपाध्यक्ष एक स्वतंत्र संवैधानिक पद पर होता है और वह अध्यक्ष के अधीन नहीं होता है। यह पद नियम समिति जैसी प्रमुख संसदीय समितियों से भी संबंधित होता है।
- तटस्थ और नषिक्रय भूमिका: निर्वाचित होने पर लोकसभा उपाध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वह दलीय संबद्धता से ऊपर उठकर कार्य करेगा तथा संसदीय प्रक्रियाओं में नषिक्रयता के साथ लोगों के विश्वास को सुदृढ़ करेगा।
- लोकतांत्रिक समावेशन एवं आम सहमतिका निर्माण: परंपरागत रूप से वषिक्रय को दिया जाने वाला लोकसभा उपाध्यक्ष का पद द्विदलीय सहयोग के लिये एक उपकरण के रूप में कार्य करता है तथा इससे आम सहमतिका आधारित राजनीति और अंतर-दलीय विश्वास को बढ़ावा मिलता है। इससे संस्थागत संतुलन को बनाए रखने संसदीय नेतृत्व में समावेशिता को बढ़ावा देने तथा विधायिका के लोकतांत्रिक लोकाचार को मजबूत करने में सहायता मिलती है।

नोट:

- किसी संसदीय समितिका सदस्य नषिक्रय होने पर लोकसभा उपाध्यक्ष स्वतः ही उस समितिका अध्यक्ष बन जाता है।

लोकसभा उपाध्यक्ष के कार्यालय के प्रभावी कामकाज के लिये कनि सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है?

- चुनाव के लिये स्पष्ट समय-सीमा: संविधान में संशोधन किया जा सकता है या एक वषिक्रय अवधि के भीतर (उदाहरण के लिये, नई लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिनों के भीतर) उपाध्यक्ष के चुनाव को अनषिक्रय करने के लिये नियम बनाए जाने चाहिये।
 - एक वैधानिक प्रावधान लाया जा सकता है, जिसके तहत राष्ट्रपतिको, निर्धारित अवधि से अधिक वलिंब होने पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, चुनाव प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार दिया जा सकता है।
- प्राधिकार का नियमिति हस्तांतरण: अध्यक्ष की उपस्थिति में भी लोकसभा उपाध्यक्ष को पीठासीन करतृत्व्यों का नियमिति हस्तांतरण संस्थागत रूप से करने से प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हो सकती है तथा कार्यालय की कार्यात्मक प्रासंगिकता की पुष्टि हो सकती है।
- स्पष्ट भूमिका संहिताकरण: वषिक्रय संसदीय नियमों या वैधानिक ढाँचे के माध्यम से लोकसभा उपाध्यक्ष की शक्तियों और ज़म्मेदारियों को परिभाषित करने से अस्पष्टता कम होगी और कार्यपालिका के प्रभाव से विधायी तटस्थता की रक्षा होगी।

नषिक्रय

भारत में लोकसभा उपाध्यक्ष का पद प्रतीकात्मक नहीं बल्कि संसदीय लोकतंत्र का एक अनषिक्रय स्तंभ है। इस पद को बनाए रखना नियम-आधारित शासन, संस्थागत अखंडता और लोकतांत्रिक लचीलेपन के सम्मान की परीक्षा है। संसद के लिये यह आवश्यक है कि वह शीघ्रता से और संविधान की भावना के अनुरूप कार्य करे।

दृष्टि मैन्स प्रश्न:

प्रश्न. लोकसभा के उपाध्यक्ष के संवैधानिक और कार्यात्मक महत्त्व पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किये जाने के लिये किये गए मतदान का कम-से-कम 50 प्रतिशत वोट पाना अनिवार्य है।
2. भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार, लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है।

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

प्रश्न. लोकसभा अध्यक्ष के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2012)

1. वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता/करती है।
2. यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु अपने निर्वाचन के छह माह के भीतर सदन का सदस्य बनना होगा।
3. यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3
(c) 1, 2 और 3
(d) कोई नहीं

उत्तर: (b)

[?/?/?/?/?]:

प्रश्न. आपकी दृष्टि में, भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहाँ तक समर्थ है? (2021)

प्रश्न. आपके विचार में सहयोग, संप्रदाय एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है? अपने उत्तर को प्रामाणिक करने के लिये कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत कीजिये। (2020)